जन धन योजना और आर्थिक विकास

डा0 विजय प्रकाष मिश्रा
अस्सिटेंट प्रोफेसर
व्यवहारिक अर्थशास्त्र विभाग
जे0 एन0पी0जी0 कालेज लखनऊ

किसी भी देष में गरीबी दूर करने में वित्तीय समावेषन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसके द्वारा ही विकास की गति बढ़ती है लेकिन यदि देष में लोग वित्तीय सेवाओं में सहभागिता नही करते है, तो इससे देष का विकास अवरूद्ध होगा। भारत में भी सरकार ने महसूस किया कि नागरिको को आर्थिक रूप से मजबूत किये बिना देष का विकास तेज गति से नही होगा इसलिये ऐसी योजना की आवष्यकता महसूस की गयी जिससे सभी लोग इससे होने वाले लाभ और विकास का हिस्सा बन सके इन सभी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन–धन योजना (PMJDY) की घोषणा की और जिसको 28 अगस्त 2014 से पूरे देष में एक साथ प्रारम्भ किया गया योजना के प्रारम्भ के समय प्रधानमंत्री जी ने इसे गरीबी को दूर करने, आर्थिक विकास को तीव्र करने के मिषन के रूप में बताया ।

प्रधानमंत्री ने जन–धन योजना को बड़े आर्थिक भागीदारी कार्यक्रम के रूप में 28 अगस्त 2014 से पूरे देष में एक साथ प्रारम्भ किया। इस अवसर को प्रधानमंत्री ने इसे एक उत्सव के तौर पर मनाने को कहा क्योंकि इसके माध्यम से देष की गरीब जनता एक कुचक्र से निजाद पाने जा रही थी। क्योंकि देष के हर नागरिक को बैंक से जोड़ने वाली जन–धन योजना में 79 मेगा षिविर और 70000 षिविर लगाये गये और इसमें कुल 18468000 खाते खोले गये इन सभी खाता धारकों को बीमा सुरक्षा भी दी गई। इस योजना का मुख्य उददेष्य सभी लोगों को बैकों से जोड़कर आर्थिक अस्पृष्यता को खत्म किया जाये। 2011 की जनगणना के अनुसार 24.67 करोड़ परिवारों में से 14.48 करोड़ परिवार तक ही बैंकिग सुविधाएँ सुलभ थी प्रधानमंत्री ने इसकी शुरूआत एक श्लोक के साथ की थी "सुखस्य मूल धर्मा, धर्मस्य मूल अर्थः , अर्थस्य मूलं राज्यं" इसका अर्थ है कि जनता को आर्थिक गतिविधियों में जोड़ने का कार्य राज्य सरकार का होता है और सरकार ने इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर ले लिया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार ने यह वादा बहुत अल्प समय में पूरा करके दिखाया है।

प्रधानमंत्री जन–धन योजना एक राष्ट्रीय मिषन है जिसका उद्देष्य आर्थिक भागीदारी को सम्भव बनाना है इस योजना के अन्तर्गत बड़े पैमाने पर आर्थिक सुविधाएँ जैसे बचत खाता खोलने की सुविधा आवष्यकतानुसार ऋण लेने की सुविधा, एक खाते से दूसरे खाते में पैसा अन्तरण करने की सुविधा बीमा तथा पेंषन आदि सुविधाएँ शामिल है।

जन–धन योजना का संक्षिप्त परिचय–यह योजना राष्ट्रीय वित्तीय समावेषन मिषन है इसके अन्तर्गत किसी भी बैंक की शाखा में अथवा आउट लेट में जीरो बैलर्स पर खाता खोला जा सकता है। बैंकों में इस योजना में करोड़ो खाते खुल चुके है और लगातार नये खाते खुल रहे है।

इस योजना में खाता खोलने वाले कई प्रकार से लाभान्वित होगें– 1) बैंक खाते में जमा राषि पर ब्याज दिया जायेगा। 2) सभी खाता धारको को एक लाख का दुर्धटना बीमा मुफ्त दिया जायेगा। 3) न्यूनतम शेष की कोई बाध्यता नही है। 4) खाता खेलने पर "रूपे" ए0टी0 एम0 कार्ड दिया जायेगा जिसका 45 दिन में कम से कम एक बार इस्तेमाल करना आवष्यक होगा। 5) यदि खाते का संचालन 6 माह तक संतोषजनक रहता है तो खातों पर 5000/– रूपये तक ओवर–ड्राफ्ट मिल सकता है। 6) पूरे देष में रू0 अन्तरण की सुविधा। 7) बीमा तथा पेंषन की भी सुविधा । 8) भविष्य में किसान क्रेडिट कार्ड को "रूपे" किसान कार्ड के रूप में जारी किये जाने के प्रस्ताव में । 9) खाता धारको को रू0 30000/– तक जीवन बीमा कवर मुफ्त मिलेगा।

समीक्षा– जन–धन योजना की प्रारम्भ तिथि 28 अगस्त 2014 से 25 नवम्बर 2014 तक प्रगति निम्नवत है–

तालिका "अ" से स्पष्ट है कि 25 नवम्बर 2014 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 345.74 लाख तथा शहरी क्षेत्रो में 290.63 लाख और कुल 636.37 लाख खाते खुले थे और जिसमें खोले गये खातों पर 452 लाख खाता धारको को रूपे डेबिट कार्ड प्रदान किये गये थे और इन खातो में शेष राषि 50217363 लाख रूपये है तथा जीरो बैलर्स वाले 475.70 लाख खाते है जो कि कुल खोले गये खातो का 74.75% है तथा सबसे अधिक खाते 144.11 लाख खाते भारतीय स्टैट बैंक में खोले गये है तथा सबसे कम महिला बैंक द्वारा केवल 0.45 लाख खाते खोले गये है।

तालिका "ब" से स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रो में 10.51 लाख तथा शहरी क्षेत्रो में 10.81 लाख खाते निजी क्षेत्र के बैंको द्वारा खाले गये है जिनकी कुल संख्या 21.32 लाख है तथा उन खातों में जमा धनराषि 37005.91 लाख रूपये है तथा जीरो बैलर्स वाले खातो की संख्या 14.07 लाख है। जो कि कुल खोले गये खातों का 66% है और इनमें 11.03 लाख खातों पर डेबिट कार्ड भी खाता धारको को प्रदान किया गया है।

तालिका "स" से स्पष्ट है कि इस अवधि में कुल 791.79 लाख खाते खोले गये जिसमें कि ग्रामीण क्षेत्रो में 470.09 लाख तथा शहरी क्षेत्रो में 361.65 लाख है तथा इन खातों में कुल जमा धनराषि 622497.83 लाख रूपये है। जीरो बैलर्स वाले 594.27 लाख खाते खोले गये जोकि कुल खोले गये खातों का 75.

05% है और इन खातों पर 482 लाख डेबिट कार्ड दिये गये। तालिका को देखने से स्पष्ट है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको द्वारा सबसे ज्यादा 636.37 लाख खाते तथा इसके बाद ग्रामीण बैंक द्वारा 134.10 लाख खाते खोले गये सबसे कम निजी क्षेत्र के बैंक को द्वारा 21.32 लाख खाते खोले गये।

तालिका "द" से स्पष्ट है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों द्वारा 134.10 लाख खाते खोले गये और इन खातों में 83318.29 लाख रूपये जमा हुये तथा जीरो बैलर्स वाले 104.5 लाख खाते खोले गये जो कि कुल खोले गये खातों का 77.92 % है। इन खातों के सापेक्ष 18.97 लाख "रूपे" डेबिट कार्ड जारी किये गये। स्टेट बैंक से सम्बन्धित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको ने सबसे ज्यादा 20.73 लाख बैंक खाते खोले गये तथा पंजाब एवं सिंध बैंक से सम्बन्धित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको में सबसे कम 0.1 लाख खाते खोले गये ।

तालिकाओं को देखने से स्पष्ट है कि मात्र 90 दिनों की अवधि में कुल 791.97 लाख खातों का खोलना प्रधानमंत्री जन–धन योजना की लोकप्रियता व जनता का सरकार के प्रति प्रेम व विष्वास का परिचायक है ।

निष्कर्ष – मनरेगा को टक्कर देने के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री जन–धन योजना शुरू कर जनता के विष्वास पर खरा उतरने का प्रयास किया है। सरकार के प्रति लोगों का विष्वास तथा आकर्षण के कारण ही पहले ही दिन 18468000 खाते खुल गये सरकार ने मार्च 2015 तक 7.5 करोड़ खाते खोलने का लक्ष्य बनाया था लेकिन आष्चर्य जनक रूप से 25 नवम्बर 2014 तक ही 7.92 करोड खाते खुल गये जिस तेजी से खाते खुल रहे है यदि यही स्थिति रही तो 2015 तक 20 करोड़ से ज्यादा खाते खुल जायेगे और यदि ऐसा हुआ तो पूरे विष्व में "आर्थिक क्रान्ति" के तौर पर जाना जायेगा और अब तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालो के भी खाते खुलने लगे है सरकार का लक्ष्य अगस्त 2018 तक 7.5 करोड़ परिवारों के 15 करोड़ खाते खुलवाना है। इस योजना का मुख्य उद्देष्य 7.64 करोड़ षहरी गरीब तथा 2.55 करोड़ ग्रामीण गरीब जिनके पास कोई बैंक खाता नही है इनके खाते खुलवाकर सामाजिक सुरक्षा तथा सब्सिडी का रूपया सीधे उनके खातो में भेजा जायेगा जब रूपया नगद बटता है तो उसमें बैइमानी का आषंका ज्यादा रहती है लेकिन जब पैसा सीधे गरीब मजदूर अषिक्षित के खाते में सीधे जायेगा तो बैइमानी में कमी आयेगी। शुरूआत रसोई गैस से की जा चुकी है और किसान कार्ड भी इसी योजना के तहत जारी होंगे मनरेगा की मजदूरी का भी भुगतान अब नगद न होकर इन खातों के माध्यम से होगे जिससे भ्रष्टाचार में कमी आने की उम्मीद है। यदि इस योजना का 80% भी लागू हो गया तो सरकार की बड़ी कामयाबी मानी जायेगी। वास्तव में प्रधानमंत्री जन–धन योजना भारतीय अर्थ व्यवस्था के लिये "मील का पत्थर" साबित होगा और इसमें प्रत्येक भारतीय का अपना खाता होगा। साथ

ही सभी खातो धारको को चेक व "रूपे" डेबिट कार्ड भी मिलेगा जिसके द्वारा समस्त सरकारी योजनाओ का सीधा लाभ खाता धारकों को मिलेगा ।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1 www.pmjdy.gov.in

2 प्रधानमंत्री जन धन योजना का ब्रोषर

3 इन्टरनेट से प्राप्त विभिन्न आकड़े एवं सूचनायें

4 इकनोमिक्स टाइम्स

5 दैनिक जागरण लखनऊ

6 भारतीय अर्थ व्यवस्था प्रतियोगिता दर्पण विषेषांक

तालिका 'अ'–सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको के द्वारा दिनांक 25 नवम्बर, 2014 तक खोले गये खाते

बैंक का नाम	खातों की संख्या			रूपये डेबिड कार्ड (लाख में)	खातों में शेष राषि (लाख में)	शून्य शेष वाले खातों की संख्या (लाख में)
	ग्रामीण	शहरी	कुल खाते			
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	59.29	84.82	144.11	82.57	13568	132.77
बैंक ऑफ बडौदा	17.46	25.11	42.57	36.8	30242	23.39
केनरा बैंक	28.19	13.73	41.92	33.96	72960.45	22.83
पंजाब नेषनल बैंक	32.59	8.2	40.8	18.28	77553.49	33.71
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	27.47	8.96	36.43	24.77	10785.51	28.64
बैंक ऑफ इंडिया	14.57	21.24	35.8	27.2	13180	26.63
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	22.69	741	30.1	26.28	11560.66	23.2
सिंडिकेट बैंक	15.64	8.54	24.18	13.29	10722.57	19.01
यूको बैंक	10.75	11.06	21.81	19.4	39595	16.36
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	12.29	8.55	20.84	12.67	34003.35	7.19
इडियंन ओवरसीज बैंक	6.42	13.09	19.51	14.88	926.38	16.3
भारतीय बैंक	11.82	7.07	18.89	18.28	5714.92	14.6
इलाहाबाद बैंक	12.81	5.75	18.56	9.49	3174.99	15.25
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	5.51	11.12	16.63	16.58	5061.34	14.13
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	9.08	6.47	15.54	10.25	48935.5	7.34
देना बैंक	8.95	5.39	14.34	11.83	6471	11.08
बीकानेर एण्ड जयपुर स्टेट बैंक	6.17	7.92	14.1	12.17	20031.4	8.84
आंध्रा बैंक	8.08	5.48	13.56	12.1	2802.67	10.73
कार्पोरेषन बैंक	6.64	6.36	13.	9.29	21625.72	5.49
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	8.41	4.11	12.52	7.64	6029.44	9.16
पंजाब एंड सिंध बैंक	5.8	3.28	9.08	7.23	24388.95	5.5
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	3.1	5.86	8.96	8.2	23106	6.18
विजया बैंक	4.37	3.46	7.82	7.01	1578.89	5.68
आईडीबीआई	3.09	3.12	6.22	4.66	1030.27	5.5
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	4.24	1.41	5.65	5.37	278.92	5.34
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	0.31	2.67	2.98	1.34	15758	0.59
भारतीय महिला बैंक	0	0.45	0.45	0.45	188.4	0.26
कुल	345.74	290.63	636.37	452.00	502173.63	475.70

तालिका 'ब'–निजी बैंको के द्वारा दिनांक 25 नवम्बर, 2014 तक खोले गये खाते

बैंक का नाम	खातों की संख्या			रूपये डेबिड कार्ड (लाख में)	खातों में शेष राषि (लाख में)	शून्य शेष वाले खातों की संख्या (लाख में)
	ग्रामीण	शहरी	कुल खाते			
एक्सिस बैंक	0.67	1.29	1.97	0.73	1188.22	1.3
सिटी यूनियन बैंक लि0	0.08	0.35	0.44	0	210.33	0.3
फेडरल बैंक	1.1	0.33	1.43	0.64	9770.97	0.75
एच0डी0एफ0सी0 बैंक	1.21	4.95	6.16	2.51	21110.06	3.74
आईसीआईसीआई बैंक	4.09	1.03	5.12	5.11	658.28	4.25
इंडसइंड बैंक	0.1	0.67	0.76	0.6	97.41	0.69
जम्मू–कष्मीर बैंक	2.27	0.53	2.8	0	3363.18	1.47
करूर वैष्य बैंक	0.04	0.55	0.6	0.51	123.23	0.49
कोटक महिन्द्रा बैंक	0.23	0.17	0.39	0.38	98.83	0.35
लक्ष्मी विलास बैंक	0.04	0.17	0.21	0	40.92	0.13
रत्नाकर बैंक	0.57	0.28	0.85	0.28	49.94	0.57
साउथ इंडियन बैंक	0.09	0.48	0.57	0.24	284.26	0
यस बैंक	0.02	0.01	0.03	0.03	10.28	0.03
कुल	10.51	10.81	21.32	11.03	37005.91	14.07

तालिका 'स'–विभिन्न बैंको के द्वारा दिनांक 25 नवम्बर, 2014 तक खोले गये खाते

बैंक का नाम	खातों की संख्या			रूपये डेबिड कार्ड (लाख में)	खातों में शेष राषि (लाख में)	शून्य शेष वाले खातों की संख्या (लाख में)
	ग्रामीण	शहरी	कुल खाते			
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	345.74	290.63	636.37	452.00	502173.63	475.10
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	113.84	20.21	134.10	18.97	83318.29	104.50
निजी बैंक	10.51	10.81	21.32	11.03	370005.91	14.07
कुल	470.09	321.65	791.79	482	622497.83	594.27

तालिका 'द'–क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के द्वारा दिनांक 25 नवम्बर, 2014 तक खोले गये खाते

बैंक का नाम	खातों की संख्या			रूपये डेबिड कार्ड (लाख में)	खातों में शेष राषि (लाख में)	शून्य शेष वाले खातों की संख्या (लाख में)
	ग्रामीण	शहरी	कुल खाते			
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	17.8	2.92	20.73	1.23	10513	14.55
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	15.98	0.26	16.24	0.44	8602.59	12.39
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	11.92	2.23	14.15	0.58	16321.31	12.38
पंजाब नेषनल बैंक	11.11	2.31	13.43	1.36	18205.9	9.93
बैंक ऑफ बडौदा	8.89	2.65	11.54	4.69	5520	9.62
बैंक ऑफ इंडिया	8.52	1.98	10.5	0.42	1132	9.83
सिंडिकेट बैंक	6.72	2.17	8.9	0.98	7733.87	7.03
बीकानेर एण्ड जयपुर स्टेट बैंक	4.89	0.16	5.05	3.95	3976.64	4.6
इलाहाबाद बैंक	4.13	0.84	4.98	0.92	548.16	3.8
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	3.73	1.06	4.8	0.17	2476.33	4.45
केनरा बैंक	2.84	1.57	4.41	1.56	215.46	2.19
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	3.31	0.17	3.49	0.47	568.84	2.84
यूको बैंक	3.18	0.08	3.26	0.13	2644	2.07
इडियंन ओवरसीज बैंक	2.92	0.09	3.01	0	1890.24	1.64
भारतीय बैंक	2.23	0.36	2.59	0	719.09	2.13
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	1.81	0.77	2.59	1.59	1125.75	1.78
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	1.24	0.43	1.67	0.18	89	1.12
देना बैंक	1.34	0.05	1.39	0.28	756	1.2
आंध्रा बैंक	0.89	0.08	0.96	0	189.74	0.76
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	0.3	0.01	0.31	0.01	87	0.17
पंजाब एंड सिंध बैंक	0.09	0.02	0.1	0.01	3.37	0.02
कुल	113.84	20.21	134.10	18.97	83318.29	104.50